(C) *Comparative Statement of order book position indicating the scheduled supply of power generating equipment for 5 years*

THERMAL SETS					HYDRO SETS					
Existing Annual installed capacity					Existing Annual installed capacity					
Sets of 210 MW 7 sets. Sets of 120 MW 3 sets. Sets of 110 MW 7 sets.					BHEL has a total installed capacity to manufacture around 1000 MW of hydro sets of various ratings. They constitute around 15 to 20 numbers on an average.					
ORDER BOOK POSITION					ORDER BOOK POSITION					
Rating (MW)	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-4981	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983
210	7	5	5	5						
120	1	1	..	..	19	11	8	6	1	Nil.
110	1	2		..						
Rating (MW)	1981-1982	1982-1983								
210		..								
120	..									
110	..	..								

बेतवा नदी पर नोटघाट पुल

466. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतवा नदी पर नोटघाट पुल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार द्वारा खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुल पर बेरियल लगा दिया है और वह चुंगी कर की वसूली कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि को तीनों सरकारों में बांटा जाएगा और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ). बेतवा नदी पर नोटघाट पुल उस राज्य सड़क पर है जो कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश में पड़ती है और जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया । परन्तु, दोनों राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पुल की लागत के कुछ भाग के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) से 8.90 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया और शेष 22.44 लाख रुपये उत्तर प्रदेश

और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) लेने से बराबर वहन किया ।

इस पुल पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पथ कर लगाया जा रहा है और 11 जून, 1976 को हुई केन्द्रीय जोनल परिषद् की 11 वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार वसूली लागत, रखरखाव व्यय आदि घट कर पथकर राजस्व की जो आय होगी वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों में बांटी जानी है ।

छुआछूत का उन्मूलन

467. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच वर्षों में देश में छुआछूत का पूरी तरह से उन्मूलन करने की अपनी नीति घोषित की है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). अस्पृश्यता की समस्या और इसके समस्त आयामों की जांच करने और कार्यवाही की रूपरेखा का सुझाव देने के लिए गृह मंत्रालय में महानिदेशक, पिछड़े वर्ग कल्याण, की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी कार्यकारी दल गठित किया गया है । कार्यवाही दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

Appointment of the Chairman of The Shipping Corporation of India

468. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to State :

(a) Whether Government have appointed the Chairman of the Shipping Corporation of India without following the laid-down procedure and norms ;

(b) if so, the facts thereof and the reasons therefor;

(c) whether candidate selected by the Public Sector Enterprises Board for the post was not approved by the Ministry for appointment and if so, the reasons therefor; and

(d) what effective steps have been taken or proposed to be taken to restructure the Shipping Corporation of India ?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) and (b). The circumstances in which the appointment was made are as follows :-

The previous Chairman-cum-Managing Director of Shipping Corporation of India was originally due to retire on 9-10-1975 on completing the age of 60 years. But actually he retired on 30-9-1977 after being given 4 extensions as the Government could not decide on his successor. Earlier, on 8-4-1976, Public Enterprises Selection Board had recommended 2 candidates for the post, but this recommendation was not implemented by the previous Government. In view of this inordinate delay and on an assessment of the need of the Corporation, the Government decided to appoint a mature and experienced publicman as part time Chairman of the Corporation and ask the PESB to recommend a suitable name for a whole time Vice Chairman-cum-Managing Director. Moreover the Managing Director has frequently to go out on Corporation's business and this arrangement would enable him to do so without detriment to the normal work at headquarters.

(c) Public Sector Enterprises Board had not recommended any candidate for this post.

(d) It is proposed to appoint full-time functional Directors to look after the various sectors of the Corporation's work so as to make available the services of high-level area specialists to the Chief Executive of the Company.